भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.4875**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते का कार्यान्वयन

4875. श्री गौरव गोगोई:

क्या **बाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है और कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे लंबित हैं;

(ख) एफटीए को अंतिम रूप देने और लागू करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(ग) भारतीय उद्योगों, निर्यात और रोजगार पर समझौते का अनुमानित प्रभाव क्या होगा?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता (एफटीए) दिनांक 13 जनवरी 2022 को शुरू की गई। अभी तक 14 दौर की वार्ता हो चुकी है। यूके की ओर से मई 2024 में उनके चुनावों के कारण वार्ता रोक दी गई थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की थी ताकि जल्द से जल्द व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के महत्व को रेखांकित किया जा सके। यूनाइटेड किंगडम के व्यवसाय और व्यापार विभाग के राज्य सचिव (एसओएस) ने दिनांक 24-25 फरवरी 2025 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठकें कीं। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दिनांक 24 फरवरी 2025 को भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की।

(ख) : भारत-यूके व्यापार वार्ताऐं एक ऐसे समझौता को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है जो व्यापक, संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी, निष्पक्ष और न्यायसंगत हो, जिससे दोनों देशों के लोगों और व्यवसायों को लाभ हो। हमारे निर्यातकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं में बाजार पहुंच सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय हित में समझौता सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी सहमत समय सीमा के व्यापार समझौते पर बातचीत की जा रही है।

(ग) : यूके के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते से चमड़ा, वस्त्र, आभूषण, समुद्री और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के निर्यात में वृद्धि होने की प्रत्याशा है। इसमें आईटी/आईटीईएस आदि जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की भी काफी क्षमता है। भारत के निर्यात और निवेश में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ सकते है। भारत-यूके व्यापार समझौता मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करने में योगदान दे सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

*****